मेहनतकशों का पैग़ाम
मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha36 5@gmail.com
www.mazdoormorcha.com
Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2024-26 /R.N.I. No. 2022007062

एफएमडीए दिखा रहा पॉड टैक्सी के हसीन सपने 3
भाजपा सरकार की षड्यंत्रकारी नीतियों के कारण बर्बादी के कगार पर 4
खट्टर सरकार अरावली में करवा रही अवैध निर्माण व खनन 5
क्रिकेट विश्वकप ने ताजा कर दी हिटलर के समय के जर्मन ओलंपिक खेलों की यादें 6
विधानसभा चुनाव में सीमा की राह में होंगे असीमित रोड़े 8

वर्ष 38 | अंक -03 | फरीदाबाद 3-9 दिसम्बर 2023 | फोन-8851091460 | 5.00 ₹

किसानों के साथ बड़ा धोखा : पेराई शुभारंभ का ढिंढोरा पीट कर चले गए मंत्री, छह दिन में ही बंद हुई मिल

हजारों टन गन्ना सूखने से बर्बाद हो रहे किसान

पलवल (मज़दूर मोर्चा) बामनी खेड़ा शुगर मिल पेराई सत्र होने के छह दिन बाद ही बंद हो गई। घोषणा और काम का ढिंढोरा पीटने में माहिर खट्टर के सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने पेराई सत्र का समारोहपूर्वक उद्घाटन करते हुए गन्ना उत्पादकों के हित में बड़ी बड़ी डींगें हांकी थीं। उद्घाटन के बाद मिल का क्या हाल है, पलट कर यह भी जानना उन्होंने गवारा नहीं किया।

एमएसपी की गांरटी कानून बनाने की मांग पर दिल्ली में धरना देने वाले किसानों को खालिस्तानी, उग्रवादी जैसी उपाधियों नवाजने वाली भाजपा के सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल यदि किसानों के हितैषी होते तो पेराई सत्र का उद्घाटन करने से ज्यादा मिल की मशीनों का सही काम करना सुनिश्चित किए जाने पर ध्यान देते। लेकिन मीडियाजीवी, धोषणावीर ढिंढोरेबाज मंत्री तो अपना नाम चमकाने आए थे। इस दौरान उन्होंने किसान हित की बड़ी बड़ी घोषणाएं कर तालियां भी बटोरीं। गर्व से बताया था कि सीएम खट्टर ने पिछले साल ही इस मिल की पेराई क्षमता बढ़ाकर 2200 टन्स केन पर डे (टीसीडी) करने की घोषणा की थी।

खट्टर ने भी घोषणा तो कर दी लेकिन न तो मंत्री और न ही अधिकारियों ने यह देखा कि पेराई क्षमता बढ़ाने के अनुपात में ही क्या मशीनरी अपग्रेड की गईं और उनके पुर्जों की क्षमता बढ़ाई गई है? घोषणा करना आसान होता है सो कर दी गई, बाकी का काम अफसर के रूप में बैठे चोरों पर छोड़ दिया गया। नतीजा वही हुआ जिसकी आशंका थी। खट्टर की घोषणा 2200 टीसीडी तो दूर मिल की मशीनें पेराई की पुरानी क्षमता यानी 1850 टीसीडी तक आने में ही खराब हो गईं। 15 नवंबर को चालू की गई मिल का टरबाइन पेराई शुरू करने के छठे दिन यानी 21 नवंबर की सुबह ही टूट गया।

मशीन किस हद तक खराब हुई इससे समझा जा सकता है कि मिल के मेकेनिक की तो छोड़िए गुडंगांव और प्रदेश के बड़े इंजीनियर भी नौ दिन बाद तक उसे सही नहीं कर सके थे।

बताते चलें कि इस शुगर मिल के दायरे में इस वर्ष 16,980 एकड़ गन्ना खेती हुई है, और इस वर्ष 32 लाख मीट्रिक टन गन्ने की पेराई का लक्ष्य रखा गया है। यदि मिल अपनी पूरी क्षमता यानी 2200 क्विंटल गन्ना प्रतिदिन से चली तो भी लक्ष्य पाने में कम से कम 145 दिन लग जाएंगे। ऐसे में दस-दस दिन तक मिल बंद रहने से दूसरे जिलों से गन्ना

शेष पेज सात पर

सुरंग हादसा : शर्म को गर्व में बदलने का खेल

उत्तरकाशी से त्रिलोचन भट्ट

41 जिन्दगियां पूरे 17 दिन अंधेरी सुरंग में फंसी रहीं, टेक्नोलॉजी के इस युग में, जब हम इस बात पर इतरा रहे हों कि हम चांद पर पहुंच गये हैं, यह शर्मनाक स्थिति है। लेकिन, बेशर्मी देखिए कि 17 दिन बाद जब सुरंग में फंसे इन मजदूरों को निकाला गया तो सरकार ने इसे इंवेंट बना दिया। कुछ संकेत स्पष्ट हैं। सरकार के पास सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने की तकनीक बेशक न हो, लेकिन शर्म को गर्व में बदलने की तकनीकी केवल इसी सरकार के पास है।

सिलक्यारा-बड़कोट सुरंग गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच है। प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले तथाकथित ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के तहत यह 4.5 किलोमीटर लंबी और 14 मीटर चौड़ी टनल बनाई जा रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच 26 कि.मी. की दूरी कम करने के लिए यह सुरंग बनाई जा रही है। इस प्रोजेक्ट में कई अन्य सुरंगे भी हैं। 12 नवंबर की सुबह इस सुरंग के अंदर भूस्खलन हो गया। करीब 60 मीटर मलबा सुरंग में आ गया और सुरंग बंद हो गई। सुरंग हालांकि दूसरी तरफ से भी बन रही है लेकिन बीच का करीब आधा किमी का हिस्सा अभी नहीं काटा गया है। इस भूस्खलन से बड़ी संख्या में मजदूर वहां फंस गये थे। पहले बताया गया कि 40 मजदूर सुरंग में हैं, बाद में यह संख्या 41 बताई गई। हालांकि इस संख्या को लेकर भी लोग अब सवाल उठाने लगे हैं।

हादसे के बाद जेसीबी से मलबा हटाकर मजदूरों को निकालने का प्रयास शुरू हुआ तो ऊपर से और मलबा आने लगा। इसके बाद यह काम बंद कर दिया गया। वर्टिकल ड्रिलिंग की बात भी मशीन न होने के कारण सिरे नहीं चढ़ी। अगले दो दिन तक तो किसी को समझ ही नहीं आया कि करना क्या है। रास्ता अंदर फंसे मजदूरों ने ही दिखाया। उन्होंने वहां लगी मोटर से पानी चला दिया। इसके बाद बाहर बैठे आपदा प्रबंधकों को समझ आया कि 4 इंच के इस पाइप का कुछ इस्तेमाल हो सकता। इस पाइप के जरिये अगले कुछ दिन तक मजदूरों से बातचीत की गई। उन्हें कुछ चना-चबेना भेजा गया और इसी पाइप से उन्हें ऑक्सीजन भी भेजा गया। बाद में एक और 6 इंच का पाइप मजदूरों तक पहुंचाने में सफलता मिली, जिसके जरिये उन्हें खिचड़ी और कुछ दूसरा जरूरी सामान भेजा जाने लगा।

मजदूरों को बाहर निकाल लिये जाने के बाद कहा जा रहा है कि यह सब मोदी और धामी के प्रयासों से संभव हो पाया। उनके दिशा-निर्देश में ही मजदूरों को इतने दिनों तक जिन्दा रखा जा सका और आखिरकार बाहर निकाला जा सका। दरअसल यदि मजदूर 17 दिन तक सुरंग में जिन्दा रहे हैं तो अपनी जीवटता के कारण रहे हैं। कोविड लॉकडाउन में जब आने-जाने के सभी साधन बंद कर दिये गये थे तो मजदूरों ने कैसा दम-खम दिखाया था, हमें याद है।

रेस्क्यू ऑपरेशन में जब भारी-भरकम मशीनें ध्वस्त हो गई और आस्ट्रेलिया से बुलाए गये कथित टनलिंग एक्सपर्ट कुछ करने के

शेष पेज दो पर

सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत को लेकर हाई कोर्ट की हरियाणा सरकार को फटकार

5 लाख का जुर्माना और मुख्य सचिव को कोर्ट के सामने व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होने के आदेश

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा)। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जज जस्टिस विनोद भारद्वाज ने बृहस्पतिवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान हरियाणा के शिक्षा विभाग को कड़ी फटकार लगाते हुए 5 लाख का जुर्माना लगाया है। सरकारी स्कूल में मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर कैथल जिले के बालू स्कूल के छात्रों ने अपने वकील प्रदीप कुमार रापड़िया के माध्यम से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार की शिक्षा विभाग से एफिडेविट के माध्यम से स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की कमी के बारे में विस्तार से जानकारी मांगी थी जिसके जवाब में जो आंकड़े व तथ्य सामने आये वो चौंकाने वाले हैं। शिक्षा विभाग द्वारा दिये गए एफिडेविट के मुताबिक हरियाणा के 131 सरकारी स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा नहीं है, 236 स्कूलों में बिजली कनेक्शन ही नहीं है, 538 स्कूलों में लड़कियों के शौचालय नहीं है और 1047 स्कूलों में लड़कों के शौचालय नहीं है। इसके अलावा कोर्ट को बताया गया कि छात्रों के लिए 8240 क्लासरूम की जरूरत है।

याचिकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील प्रदीप रापड़िया और रिपुदमन बूरा ने हाई

शेष पेज सात पर

46 करोड़ की लागत से 19 स्कूलों का आधुनिकीकरण

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) पूरे हरियाणा में चंद सरकारी स्कूल ही ऐसे होंगे जिनमें शौचालय, पेयजल, बिजली व बैठने की उचित व्यवस्था हो; पुस्तकालय, साइंस लैबोरेट्री व खेल-कूद की तो बात ही छोड़ दीजिए। बीते सप्ताह हाईकोर्ट की फटकार के बाद जुमलेबाज़ खट्टर सरकार ने पूरे हरियाणा की बात न करके केवल फ़रीदाबाद के मात्र 19 स्कूलों में कुछ सुधार की घोषणा की है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली की तरह यहां भी बहुमंजिला स्कूल बनाए जायेंगे। इनमें तमाम आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके लिये 46 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

शेष पेज सात पर